भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1356
मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण

†1356. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सहकारी बैंकों को डिजिटल बनाने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त प्रस्ताव के संबंध में अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हाँ, मान्यवर। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधिदेश के अनुसार, सभी सहकारी बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर कार्य कर रहे हैं। शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रचालन कार्यकुशलता और अत्याधुनिक आईटी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर अम्ब्रेला संगठन की स्थापना के लिए अपनी विनियामक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस संबंध में शहरी सहकारी बैंकों के लिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (NUCFDC) नामक एक अम्ब्रेला संगठन का गठन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08.02.2024 को नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (NUCFDC) को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) इस उद्देश्य से प्रदान किया है कि वह सामूहिक शक्तियों, तकनीकी समीक्षा, सहभागिता वर्धन, नवाचार प्रोत्साहन का लाभ लेकर शहरी सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण को गति और सदस्य बैंकों की डिजिटल युग की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से समझने में तैयारी सुनिश्चित करे। इस अम्ब्रेला संगठन को भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन स्व-विनियामक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए 300 करोड़ रुपए की चुकता पूँजी प्राप्त करनी होगी । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने चुकता पूँजी के 20% के योगदान पर अपनी सहमति दी है।

इसी प्रकार नाबार्ड, जो ग्रामीण सहकारी बैंकों की पर्यवेक्षी एजेंसी है ग्रामीण सहकारी बैंकों के आईटी अवसरंचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय और RBI के निकट समन्वय से नाबार्ड ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिए शेयर्ड सर्विसेज एंटिटी (SSE) की स्थापना का एक प्रस्ताव तैयार किया है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पैक्स को सशक्त करने के लिए कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना अनुमोदित की गई है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहाकरी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । अब तक इस परियोजना में 794 करोड़ रुपए (लगभग) संवितरित किए गए हैं।

सरकार द्वारा दीर्घकालिक सहकारी क्रेडिट सरंचना को सशक्त करने के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना अनुमोदित की गई है। इस संबंध में हार्डवेयर की खरीद, डिज़िटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में भारत सरकार के हिस्से के रूप में 08 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 4.26 करोड़ रुपए की धनराशी जारी की गई है।

*****